

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

- (1) अमृतलाल पुत्र मगनलाल जी, जाति- सुथार, निवासी- जावाल, तहसील व जिला- सिरोही
- (2) ग्राम पंचायत जावाल, वर्तमान में: नगर पालिका, जावाल जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 71/2022

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली, अप्रार्थी संख्या- 1(एक) की ओर से
3. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 25 मई, 2023

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 15.7.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशनामा उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया।
- (3) बहस सुनी गई। विद्वान परोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जिस भूमि का आवासीय पट्टा संख्या 10 दिनांक 15.7.2020 को जारी किया गया है वह विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या- 1(एक) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 765 किस्म गोचर भूमि दर्ज है। यह कि जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo moto के तहत प्रकरण दर्ज कर जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक:सतर्कता/ 33(14)()बैठक/ 2021/185 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक/सतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा दिनांक 01.01.2020 के पश्चात् जारी पट्टों में से 42 पट्टे गोचर भूमि एवं 15 पट्टे प्रतिबंधित राजकीय भूमि एवं निजी खातेदारी भूमि में जारी किये गये। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त 57 पट्टे

.....पेज दो पर



अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

अवैधानिक रूप से जारी किये जाने से उक्त गैर विधिक पट्टों को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक:मा.ज.सु/स.प्र. (32)/2022/76 दिनांक 01.6.2022 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को अधिकृत किया गया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की उक्त रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 22.3.2022 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में आवासीय पट्टा गोचर भूमि में जारी किया गया है, जो की प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को जांच के दौरान प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध नहीं करवाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना नहीं किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा गोचर भूमि में पट्टा जारी किया जाना अवैधानिक एवं पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.3.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का आवासीय मकान पाया गया जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या-1 (एक) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या-1(एक) को अनुचित लाभ देने की नियत से उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त निगरानी उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पत्रांक/सतर्कता/33(14)0बैठक/2021/185 दिनांक 13-12-2021 की पालना में प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के सारांश पद संख्या 4,5,6 एवं 7 (पेज संख्या 4 व 5) में जांच अधिकारी द्वारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को घोर अनियमितता, पद का दुरुपयोग करने एवं विकास अधिकारी, प.स. सिरोही द्वारा गंभीर प्रकृति के प्रकरण में लापरवाही बरतने, दोषी कार्मिकों, जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने एवं दोषियों को संरक्षण देने का कार्य करने की पुष्टी की गई है परिणामस्वरूप तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाने एवं विकास अधिकारी पं.स. सिरोही के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गई है। लेकिन उच्च स्तरीय जिला प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण में तत्कालीन सरकारी कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की है सिर्फ गरीब और बेकसूर जनता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है। जब तक उक्त जांच रिपोर्ट में आदेशित कार्यवाही की पूर्ण पालना नहीं की जाती, तब तक उपरोक्त अनवाणी प्रकरण एवं ऐसे अन्य सभी प्रकरणों में सच्चा न्याय नहीं हो पाएगा। यह कि अप्रार्थी सं. 2 (सरपंच ग्राम पंचायत, जावाल) द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में उपरोक्त पट्टा संख्या 10 बुक सं. 539 मिसल संख्या 77 दिनांक 15-07-2020 सही एवं विधिपूर्ण प्रक्रिया के पुराने पुश्तैनी हक स्वामित्व मानते हुए

.....पेज तीन पर



a
जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सम्पूर्ण मिसल मय पत्रावली प्रक्रिया के तहत मौके पर जांच कर पुराना पुश्तैनी मकानात हक बतौर साक्ष्य मानते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा नियमानुसार जारी किया हुआ है जिसका पंजीयन अप्रार्थी द्वारा उपपंजीयक कार्यालय सिरोही में दिनांक 02-09-2020 को करवाया है जो लेख पत्र संख्या 1228 पर दर्ज है। पूर्ववर्ती अलग अलग ग्राम पंचायतों द्वारा प्रार्थी को पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन एवं मकान निर्माण की स्वीकृति बाद जांच जारी की गई है। अप्रार्थी पिछले कई वर्षों से अपने पुरे परिवार के साथ वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर निवास कर रहे हैं। एवं प्रश्नगत भूमि के आस पास चारों तरफ ग्राम जावाल की मुख्य एवं पुरानी आबादी बसी हुई है जिसमें लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से पक्के मकान, दुकान निर्माण करवाए हुए है। इस प्रकार मौका स्थिति एवं पट्टा दस्तावेज के आधार पर यह पूर्णतया साबित है की अप्रार्थी संख्या-1 (एक) प्रश्नगत भूमि पर कंदीमी से काबिज है। अप्रार्थी संख्या-1 ने अपने मकान का पक्का निर्माण किया हुआ है एवं अप्रार्थी ने उक्त मकान में बिजली के कनेक्शन अपने नाम से ले रखे है। प्रश्नगत भूमि मौके पर पुरानी बसी हुई आवासीय आबादी कॉलोनी के रूप में ग्राम पंचायत जावाल (वर्तमान में नगरपालिका जावाल) का हिस्सा है एवं उक्त भूमि के आस पास में चारों तरफ आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, सरकारी विद्यालय स्थिति है जो की ग्राम जावाल की सबसे पुरानी आबादी भूमि है जिसमें अडीस-पडोस में कई लोगो द्वारा निर्मल भारत योजना के अंतर्गत निजी शौचालय व मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मकान निर्माण किये हुए है उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 व अन्य करीब 500 परिवार पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से निवास कर अपना जीवन यापन कर रहे है। ग्राम जावाल सिरोही तहसील का सबसे बड़ा व्यापारिक कस्बा है एवं प्रश्नगत भूमि ग्राम जावाल की पुरानी मुख्य आबादी भूमि हैं जिसमें ग्राम जावाल के बाशिंदे कंदीमी समय से प्रश्नगत भूमि पर निवास करते आ रहे है और अगर किसी त्रुटीवश राजकीय रेकॉर्ड में प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि नहीं होकर राजस्व भूमि के रूप में दर्ज हैं तो यह पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत, प्रशासन एवं राजस्व विभाग की लापरवाही एवं असफलता का ही नतीजा है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में ग्राम पंचायतों को जरूरत के अनुसार आबादी भूमि आवंटन करने के नियम बना रखे है एवं समय समय पर आदेश व परिपत्र जारी कर ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन करने के निर्देश दिये गये है, उक्त आदेश व परिपत्र प्रभावी होने बावजूद ग्राम जावाल की पुरानी एवं मुख्य आबादी भूमि राजस्व रेकॉर्ड में आबादी दर्ज न होकर गोचर के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा की हुई लापरवाही को न दोहराते हुए जिला कलेक्टर महोदय को विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 257 के अन्तर्गत निर्मित नियम 7 में यह अधिकार प्राप्त है की वह संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका से विचार विमर्श कर चारागाह भूमि की किस्म को परिवर्तन कर और उसके बदले अन्य भूमि सेटपार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए व 92 के अनुसार जिला कलेक्टर को आबादी विकास हेतु भी भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। यह भी महत्वपूर्ण है कि विवादित खसरा भूमि में से ही जनहितार्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पटवार घर, पुलिस चौकी व अन्य राजकीय कार्यों हेतु भूमि सेट अपार्ट कर आवंटित की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य ही आस पास बसे ग्रामीणों को सरकारी सेवायें/योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है? अगर कंदीमी समय से निवासरत उन सभी लोगों को वहां से एक साथ हटाया जाता है तो उपरोक्त सरकारी कार्यालयों को प्रश्नगत जगह पर स्थापित करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अगर अप्रार्थी संख्या-1 की प्रश्नगत पट्टाशुदा भूमि राजस्व विभाग में त्रुटीवश गोचर भूमि के रूप में दर्ज है तो आस पडोस के अन्य सभी सरकारी कार्यालय भी अवैध है।

....पेज चार पर



अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

विवादित खसरा भूमि कभी भी चारागाह हेतु उपयोग में नहीं आ रही है, केवल मात्र आवासीय व्यवसायिक सरकारी भवनों हेतु ही उपयोग में ली जा रही है। जीवन जीने एवं आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) सपठित अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रदत्त मूलभूत अधिकार है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दृष्टांत **Rajesh yadav vs State of UP** में यह प्रतिपादित किया है कि आश्रय का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है एवं राज्य का यह मानवाधिकार एवं संवैधानिक कर्तव्य है कि समाज के गरीब एवं कमजोर तबके के लोगो के रहने के लिए राज्य अपने स्ट्रॉत में से आवास उपलब्ध करवाए। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन खारिज कर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के मूलभूत व विधिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1(एक) के अधिकारों की रक्षा कर एवं विधि में दिए गये प्रावधान अनुसार वादग्रस्त भूमि की किस्म को रिकर्ड में गोचर से आबादी में परिवर्तन कर अप्रार्थी संख्या-1(एक) के हितो को संरक्षित कर उनसे नियमानुसार शुल्क वसूलकर उनके पक्ष में जारीशुदा पट्टे को यथावत आबाद रखे जाने के आदेश प्रदान करावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा जारी किया गया है, अतः प्रकरण में न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 10 दिनांक 15.7.2020 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं उन्हें राजस्थान पंचायती वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

- (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अधधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-
- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)
- (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)
- (ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

.....पेज पांच पर



a
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक:सर्तकता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरौही को प्रेषित जांच रिपोर्ट (जो जिला जन अभाव अभियोग एवं सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo Moto दर्ज प्रकरण के संबंध में एवं जिला कलेक्टर, सिरौही के पत्र क्रमांक:सर्तकता/33(14)0 बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित की गई है) की छाया प्रति एवं इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित दस्तावेज उप तहसीलदार, कालन्दी की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी, सिरौही द्वारा गठित टीम (जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल, पटवारी हल्का जावाल, पटवारी हल्का सनपुर व पटवारी हल्का आमलारी समिलित है) की मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जिस भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 765 किस्म गोचर भूमि दर्ज है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने का कानून कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में गोचर भूमि का पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार, सिरौही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरौही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी अमृतलाल पुत्र मगनलाल जी, जाति- सुथार, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 15.7.2020 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरौही